भाजपा विधायक दल की बैठक में फ्लोर मैनेजमैंट पर विस्तार से चर्चा हुई

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विपक्ष के आरोपों का संयमित तरीके से जवाब देने की सलाह दी

जयपुर, 19 अगस्त। राजस्थान विधानसभा का मानसून सत्र गुरुवार से शुरू होने जा रहा है। सत्र से ठीक पहले बुधवार को मुख्यमंत्री निवास (सीएमआर) में भाजपा विधायक दल की अहम बैठक हुई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई बैठक में सरकार ने सदन के भीतर विपक्ष के सवालों और संभावित हमलों का जवाब देने के साथ ही अपनी उपलब्धियों को प्रभावी तरीके से रखने की रणनीति पर मंथन किया।

- **सूत्रों के अनुसार, विपक्ष की ओर से उठाये जाने वाले संभावित मुद्दों, सरकार के मंत्रियों व विधायकों की भूमिका तथा सदन में एकजुटता बनाए रखने के लिए दिशा-निर्देश दिये गए।**

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को भाजपा विधायक दल की बैठक ली। इस दौरान बैठक में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़, संगठन महामंत्री अजेय कुमार, राष्ट्रीय महामंत्री हरीश द्विवेदी, उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी और डॉ. प्रेमचंद बैरवा सहित मंत्रिपरिषद के सदस्य एवं भाजपा विधायक मौजूद रहे।

बैठक में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़, संगठन महामंत्री अजेय कुमार, राष्ट्रीय महामंत्री हरीश द्विवेदी, उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी और डॉ. प्रेमचंद बैरवा, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग सहित, मंत्रिपरिषद के सदस्य और भाजपा विधायक मौजूद थे।

बैठक में मानसून सत्र के दौरान फ्लोर मैनेजमेंट को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। विपक्ष की ओर से उठाए जाने वाले संभावित मुद्दों, सरकार के मंत्रियों और विधायकों की भूमिका तथा सदन में एकजुटता बनाए रखने को लेकर दिशा-निर्देश दिए गए।

सरकार की ओर से यह रणनीति बनाई गई कि विपक्ष को सरकार को घेरने का कोई ऐसा अवसर नहीं दिया जाए, जिससे सदन में राजनीतिक दबाव की स्थिति बने।

बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भाजपा विधायकों को सदन की कार्यवाही के दौरान सरकार के पक्ष को मजबूती से रखने और विपक्ष के आरोपों का संयमित तरीके से जवाब देने पर जोर दिया। पार्टी नेतृत्व की कोशिश है कि मानसून सत्र में सरकार की राजनीतिक और प्रशासनिक उपलब्धियां प्रमुखता से सामने आएं और विपक्ष के मुद्दों का प्रभावी तरीके से जवाब दिया जा सके।

गुजरात में नकली "रॉयल स्टैग" शराब से 3 की मौत

भावनगर (गुजरात), 19 अगस्त। भावनगर जिले में नकली 'रॉयल स्टैग' ब्रांड की शराब का कहर बरपा है। जहरीली शराब के सेवन की आशंका के बीच दो और लोगों की मौत होने से मृतकों की संख्या बढ़ कर तीन पहुंच गई है। जिला कलेक्टर के अनुसार, फिलहाल सिविल अस्पताल में 8 और निजी अस्पतालों में भर्ती मरीजों की हालत सामान्य है।राज्य सरकार ने घटना की जांच स्टेट मॉनिटरिंग सेल (एसएमसी) को सौंप दी है।एसएमसी के एसपी मयूर चावड़ा को तत्काल भावनगर भेजकर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस जांच में सामने आया है कि घोघा तहसील के खरकड़ी गांव में 16 अगस्त की रात सात दोस्तों ने शराब पार्टी की।

असम के 115 ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

3206 हेक्टेयर कृषि भूमि पानी में डूबी हुई है। बाढ़ से बड़े पैमाने पर सड़क, पुल एवं अन्य आधारभूत ढ ांचे को नुकसान पहुंचा है।

सपा नेता आजम खान के दस ठिकानों पर ईडी ने छापे मारे

यह कार्यवाही मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट एवं विश्वविद्यालय से जुड़े मनी लॉण्ड्रिंग मामले में की गई

लखनऊ, 19 अगस्त। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं।

इसी क्रम में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के लखनऊ जोनल ऑफिस ने बुधवार को आजम खान के 10 ठिकानों पर छापेमारी की। रामपुर से लेकर सहारनपुर और दिल्ली तक 10 ठिकानों पर यह कार्रवाई चल रही है।

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, यह कार्रवाई मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट और मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय, रामपुर से जुड़ी मनीलॉड्रिंग मामले की चल रही जांच के सिलसिले में है। धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 की धारा 17 के तहत, ईडी की कार्रवाई चल रही है। जांच में कॉन्ट्रैक्र्स और ट्रस्ट के बीच पैसे के लेनदेन और अन्य जानकारियां मिली हैं। जांच एजेंसियां इस बात का पता लगाने का प्रयास कर रही हैं कि ट्रस्ट को जो फंड मिला है वह वैध है या नहीं। साथ ही इन पैसों का इस्तेमाल विश्वविद्यालय के काम में किया गया है या कहीं और इसका इस्तेमाल हुआ।

- **जांच एजेंसियां इस बात का पता लगा रही हैं कि ट्रस्ट को जो फंड मिला, वो वैध है या नहीं। साथ ही इन पैसों का उपयोग विश्वविद्यालय के काम में किया गया या कहीं और खर्च हुआ।**

उल्लेखनीय है कि आजम खान के मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट का मुख्यालय लखनऊ में है, जिसके मुख्य ट्रस्टी सपा नेता आजम खान ही हैं। उनके अलावा परिवार के कुछ सदस्य और सहयोगी भी ट्रस्ट में शामिल हैं। यह ट्रस्ट रामपुर जिले में मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय और एक पब्लिक स्कूल का भी संचालन करता है।

जुलाई, 2026 में रामपुर विकास प्राधिकरण (आरडीए) की ओर से विश्वविद्यालय की 40 में से 38 इमारतों को गिराने का आदेश जारी हुआ था। जिसे लेकर काफी विवाद हुआ और बाद में इस पर अंतरिम रोक लगा दी गई।

परीक्षा रद्द हुई, नियुक्त कर्मियों को हटाने के आदेश को अदालत में चुनौती

याचिका के अनुसार 11 वीं से 13 वीं जेपीएससी परीक्षा में सफल 342 अभ्यर्थी नौकरी कर रहे हैं

रांची, 19 अगस्त । झारखंड सरकार की ओर से 11वीं से 13वीं जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के आधार पर नियुक्त कर्मियों को हटाने के आदेश को झारखंड उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता सोनम कुमारी ने सरकार की उस अधिसूचना को चुनौती दी है, जिसमें विज्ञापन संख्या 1/2024 के तहत आयोजित 11वीं से 13वीं जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा को रद्द कर दिया गया है।

याचिका में सोनम कुमारी ने कहा है कि उन्होंने दूसरी जगह की नौकरी छोड़कर झारखंड में परीक्षा दी थी। उन्हें 24 नवंबर 2025 को नियुक्ति पत्र मिला था और उन्होंने प्रशिक्षण भी पूरा किया। इसी बीच राज्य सरकार ने 18 अगस्त 2026 को अधिसूचना जारी कर उनकी नियुक्ति रद्द कर दी। याचिकाकर्ता ने नियुक्ति रद्द करने संबंधी सरकार के आदेश को निरस्त करने का आग्रह उच्च न्यायालय से किया है। बताया गया है कि इस परीक्षा में सफल 342 अभ्यर्थी वर्तमान में नौकरी कर रहे थे। उल्लेखनीय है कि सीआईडी जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर राज्य सरकार ने टीडीपीएल से जुड़ी सभी परीक्षाओं को रद्द करने की घोषणा की थी। इसके अलावा वर्ष 2014 से आयोजित सभी नियुक्ति परीक्षाओं में संभावित अनियमितताओं को देखते हुए जांच कराने का भी निर्णय लिया गया है।

- **झारखंड सरकार की अधिसूचना में 22 परीक्षाओं को रद्द करने, 6 वी प्रक्रिया स्थगित करने तथा 18 परीक्षाओं को जांच के दायरे में शामिल किया गया है।**

इसी के मद्देनजर कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ने परीक्षाएं रद्द करने, परीक्षा प्रक्रिया स्थगित करने और जांच कराने से संबंधित अधिसूचना जारी की है। अधिसूचना में 22 परीक्षाओं को रद्द करने, छह परीक्षाओं की प्रक्रिया स्थगित करने और 17 परीक्षाओं को जांच के दायरे में शामिल करने का उल्लेख किया गया है।

जेपी नड्डा को ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

अस्पताल में चिकित्सकीय निगरानी में रहने के बाद उनकी स्थिति लगातार बेहतर होने पर डॉक्टरों ने उन्हें डिस्चार्ज कर दिया।

ट्रिब्यूनल बेटे-बहु को संपत्ति से बेदखल कर सकता है -सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, 19 अगस्त। उच्चतम न्यायालय ने वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों को लेकर एक अहम फैसले में साफ कहा है कि अगर किसी बुजुर्ग के भरण-पोषण, सुरक्षा और सम्मान के लिए जरुरी हो तो संबंधित ट्रिब्यूनल उनकी संपत्ति से बेटे-बहू को बेदखल करने का आदेश दे सकता है। जस्टिस पीएस नरसिम्हा की अध्यक्षता वाली बेंच ने ये आदेश दिया।

कोर्ट ने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा और गरिमा सुनिश्चित करना कानून का अहम उद्देश्य है। उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालय के उस फैसले को भी रद्द कर दिया, जिसमें बेटे और बहू को संपत्ति से बाहर करने के ट्रिब्यूनल के आदेश को रद्द कर दिया गया था।

मामला लखनऊ के विकास नगर स्थित एक मकान से जुड़ा हुआ है। मकान के मालिक रविकांत गुप्ता ने अपने बेटे के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। गुप्ता का आरोप था कि उनके बेटे ने 81 वर्षीय उनकी मां यानी अपनी दादी को घर में नहीं रहने दिया और कथित तौर पर उन्हें घर छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। इसके बाद बुजुर्ग महिला को वृद्धाश्रम जाना पड़ा।

व्यवस्था मजबूत दिखती है, पर स्थाई व संस्थागत रुप देना जरुरी

नई दिल्ली, 19 अगस्त। उच्चतम न्यायालय ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) को निर्देश दिया है कि वह नीट परीक्षा में सुधारों को संस्थागत रूप दे। जस्टिस पीएस नरसिम्हा की अध्यक्षता वाली बेंच कहा कि कागज पर तो व्यवस्था मजबूत दिखती है लेकिन इसे स्थायी और संस्थागत रुप देना जरुरी है।

मामले की सुनवाई के दौरान बुधवार को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने परीक्षा प्रक्रिया का विस्तृत ब्यौरा दिया।

केन-बेतवा लिंक के खिलाफ सत्याग्रह को राहुल गांधी ने समर्थन दिया

नई दिल्ली/भोपाल, 19 अगस्त। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष एवं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश की दो नदियों को जोड़ने वाली प्रस्तावित केन-बेतवा नदी-लिंक परियोजना के खिलाफ सत्याग्रह कर रहे आदिवासियों को समर्थन दिया है। उन्होंने कहा कि इस लड़ाई में वे आदिवासी भाई-बहनों के साथ हैं। वे इस मुद्दे को लोकसभा में उठाएंगे।

मध्य प्रदेश के छतरपुर में केन-बेतवा लिंक परियोजना के खिलाफ चल रहे आंदोलन के प्रमुख कार्यकर्ता अमित भटनागर ने आंदोलनकारी आदिवासियों के साथ बुधवार को नई दिल्ली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने प्रोजेक्ट से प्रभावित आदिवासी परिवारों की समस्याओं, विस्थापन, पुनर्वास और अधिकारों से जुड़े मुद्दों को राहुल गांधी के सामने रखा। मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट और वीडियो साझा कर आंदोलनकारियों के संघर्ष का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि अपने जायज हक की लड़ाई लड़ रहे बुंदेलखंड के निवासी सम्मान और समर्थन के हकदार हैं। राहुल ने भरोसा दिलाया कि आदिवासी परिवारों की इस लड़ाई में वे और कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी है। राहुल गांधी ने आंदोलनकारियों को भरोसा दिलाया कि उनके पुनर्वास, भूमि अधिकार और जबरन बेदखली के खिलाफ आवाज को संसद में प्रमुखता से उठाया जाएगा।

- **परियोजना के खिलाफ आंदोलन के प्रमुख कार्यकर्ता अमित भटनागर बुधवार को राहुल गांधी से मिले**

कोलकाता : होटल की तीसरी मंजिल की आग में 9 की मौत

आग इतनी तेजी से फैली कि आसपास के कई होटल चपेटे में आ गये

कोलकाता, 19 अगस्त। कोलकाता के फ्री स्कूल स्ट्रीट इलाके में मंगलवार देर रात एक होटल में आग लगने से नौ लोगों की मौत हो गई। आग इतनी तेजी से फैली कि आसपास के कई होटल भी इसकी चपेट में आ गए। धुएं से दम घुटने के कारण कई लोग बेहोश हो गए, जिन्हें मौके से निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया। घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई।

स्थानीय लोगों के अनुसार, रात दो बजे से कुछ पहले होटल की तीसरी मंजिल पर आग लगी। देखते ही देखते होटल के कमरों में धुआं भर गया और आग आसपास के हिस्सों तक फैल गई। होटल में ठहरे लोगों में भगदड़ मच गई और लोग जान बचाने के लिए बाहर निकलने की कोशिश करने लगे।

- **होटल संकरी गली में होने के कारण दमकल की गाड़ियों को काफी अंदर तक ले जाना संभव नहीं था। शुरुआत में दमकलकर्मियों ने बाहर से ही आग बुझाने की कोशिश की।**

दमकल विभाग को रात 2 बजकर 7 मिनट पर आग लगने की सूचना मिली। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। न्यू मार्केट थाने की पुलिस और आपदा प्रबंधन दल भी घटनास्थल पर पहुंच गये। होटल संकरी गली में स्थित होने के कारण दमकल की गाड़ियों को काफी अंदर तक ले जाना संभव नहीं था। ऐसे में दमकलकर्मियों ने शुरुआत में बाहर से आग बुझाने की कोशिश की। बाद में वे होटल के भीतर दाखिल हुए और बड़े पैमाने पर बचाव अभियान चलाया। दमकल विभाग के शुरुआती अनुमान के मुताबिक, आग शॉर्ट सर्किट के कारण लग सकती है।

राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ने कोलकाता अग्निकांड पर दुःख जताया

नई दिल्ली, 19 अगस्त। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कोलकाता के फ्री स्कूल स्ट्रीट इलाके में मंगलवार देर रात एक होटल में आग लगने से नौ लोगों की मौत पर गहरा शोक व्यक्त किया। राष्ट्रपति ने बुधवार को कोलकाता अग्निकांड में हुई जानमाल की हानि पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि कोलकाता में आग लगने की दुर्घटना में लोगों की मृत्यु का समाचार अत्यंत दुखद है। उन्होंने शोक संपत्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की।

प्रधानमंत्री मोदी ने अग्निकांड पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि दुख की इस घड़ी में उनकी संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ हैं।

हाथी नहीं गणेश हैं... ब्रह्मा, विष्णु ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

चर्चा और चिंता शुरू हो गई है। बहुजन समाज के लोगों से इन राजनीतिक रणनीतियों के प्रति सतर्क रहने की अपील की।

मायावती ने आगामी चुनावों में सवर्ण समुदायों से और अधिक उम्मीदवार उतारने का वादा किया है।

2007 में मायावती की शानदार जीत का श्रेय उस व्यापक सामाजिक गठबंधन को दिया गया था, जिसमें उन्होंने ब्राह्मणों और अन्य सवर्ण जातियों के एक बड़े हिस्से को अपने साथ जोड़ लिया था।

2007 में बसपा ने 206 विधानसभा सीटें जीती थीं और उसे 30 प्रतिशत से अधिक वोट मिले थे। लेकिन इसके बाद हुए चुनावों में पार्टी लगातार कमज़ोर होती गई।

2022 के विधानसभा चुनाव में बसपा का वोट शेयर 12 प्रतिशत से नीचे चला गया और पार्टी केवल एक विधानसभा सीट जीत सकी।

2024 के लोकसभा चुनाव में मायावती की पार्टी उत्तर प्रदेश में एक भी सीट नहीं जीत सकी और उसका वोट शेयर 10 प्रतिशत से नीचे आ गया।

मायावती की ब्राह्मणों को दोबारा अपने पाले में लाने की कोशिश को 2007 के पुराने गौरव को वापस पाने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है।

उत्तर प्रदेश के मतदाताओं में ब्राह्मणों की हिस्सेदारी करीब 10 प्रतिशत है और पिछले कई चुनावों में उनका भारी बहुमत भाजपा के पक्ष में जाता रहा है। इस साल जनवरी में अपने जन्मदिन के अवसर पर दिए गए भाषण में भी मायावती ने मतदाताओं को बसपा सरकारों के दौरान ब्राह्मणों को मिले राजनीतिक महत्व और प्रतिनिधित्व की याद दिलाई थी।

उन्होंने आरोप लगाया था कि भाजपा के शासन में इस समुदाय की उपेक्षा हो रही है।

क्या भाजपा का ब्राह्मण वोट बैंक टूटेगा?

लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या मायावती का बार-बार 2007 की सफलता का हवाला देना उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों और भाजपा के बीच मजबूत राजनीतिक संबंध को कमजोर कर पाएगा?

"सीएसडीएस-लोक नीति" के आंकड़ों के अनुसार, 2022 के विधानसभा चुनाव में 89 प्रतिशत ब्राह्मणों ने भाजपा को वोट दिया था। इसके अलावा 87 प्रतिशत ठाकुर/राजपूत, 83 प्रतिशत वैश्य और 78 प्रतिशत अन्य सवर्ण मतदाताओं ने भी भाजपा का समर्थन किया था।

इसके साथ ही बसपा के सामने दलित वोटों के भाजपा की ओर खिसकने की चुनौती भी है।

राज्य के कुल मतदाताओं में 20 प्रतिशत से अधिक हिस्सेदारी रखने वाले दलितों का एक वर्ग पिछले कुछ चुनावों में भाजपा की ओर गया है। मायावती की बसपा को लेकर यह धारणा मजबूत हुई है कि वह एक जनआंदोलन से बदलकर एक व्यक्ति-केन्द्रित पार्टी बन गई है।

दूसरी ओर, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव भी अपने "पीडीए", पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के नारे के जरिए दलित मतदाताओं को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं।

लोकसभा चुनाव में यह रणनीति सपा के लिए सफल रही थी और पार्टी ने भाजपा को चौंकाते हुए उत्तर प्रदेश में शानदार प्रदर्शन किया था।

प्रदेश में सरकारी स्कूल के बच्चों ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

65,000 सरकारी स्कूलों में 69 लाख से अधिक स्कूली बच्चों को लाभ पहुंचाना है। इस योजना के तहत प्राथमिक और उच्च प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को गर्म दूध उपलब्ध कराया जाता है। लेकिन शिक्षा विभाग के आंतरिक आंकड़ों के अनुसार, राज्यभर में दूध पाउडर की आपूर्ति 58 प्रतिशत कम हो रही है। यह स्थिति बताती है कि खरीद से लेकर भुगतान, परिवहन और निगरानी तक पूरी आपूर्ति श्रृंखला कई स्तरों पर प्रभावित हुई है।

हाल की तीन महीने की निगरानी अवधि में राजस्थान ने अनुमान लगाया कि योजना के लिए 3,756.43 मीट्रिक टन स्किम्ड मिल्क पाउडर की आवश्यकता है। इसके मुकाबले केवल 1,573.81 मीट्रिक टन, यानी आवश्यकता का 41.9 प्रतिशत ही उपलब्ध हो पा रहा है।

कम से कम 41 में से 17 शैक्षणिक जिलों में स्कूलों तक दूध पाउडर की कोई आपूर्ति नहीं हुई। पता चला है कि अलवर, भरतपुर, उदयपुर, बीकानेर और कोटा जैसे कई प्रमुख जिलों में दूध वितरण पूरी तरह बंद है।

तत्काल समस्या सरकार की खरीद और वितरण व्यवस्था के भीतर दिखाई देती है। राज्य शिक्षा विभाग और राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन (आरसीडीएफ) सुचारू आपूर्ति व्यवस्था बनाए रखने में विफल रहे हैं। कथित तौर पर कई महीने पहले आवंटन मंजूर हो चुके थे, लेकिन खरीद और वितरण प्रक्रिया अटकी रही। डेयरी फैडरेशनों को किए जाने वाले लंबित भुगतान ने स्थिति को और जटिल बना दिया।

- **इसके अलावा स्कूलों में दूध पाउडर का एक्सपायरी डेट स्टॉक भी पड़ा है।**
- **इस योजना के तहत राजस्थान सहकारी डेयरी संघ अतिरिक्त दूध खरीद कर उसका पाउडर बनाता है। वह पाउडर स्कूलों में भेजा जाता है, यहाँ गर्म पानी मिलाकर पाउडर से दूध बना कर बच्चों को दिया जाता है।**

इसके अलावा, दूध पाउडर की कालाबाजारी का भी खतरा सामने आया है। जाँच से पता चला कि जब सरकारी स्कूल दूध के लिए जूझ रहे हैं, वहीं बच्चों के लिए निर्धारित कुछ स्टॉक को कथित तौर पर व्यावसायिक बाजार में भेजा जा रहा था।

जयपुर जिले के चीथवाड़ी गांव में पुलिस ने एक वाहन को पकड़ा, जिसमें करीब 3,000 किलोग्राम सरकारी दूध पाउडर ले जाया जा रहा था। बताया गया कि इन बोरियों पर लिखा था "बिक्री के लिए नहीं, केवल स्कूल आपूर्ति के लिए।"

आरोप है कि इस दूध पाउडर को व्यावसायिक स्तर पर मावा (खोया) बनाने वाले निर्माताओं तक पहुंचाया जा रहा था।

इसके बाद आरसीडीएफ ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और एफआईआर दर्ज की गई। जांचकर्ताओं ने पाया कि कथित तौर पर स्कूलों की उपस्थिति के रिकॉर्ड में हेरफेर करके दूध की अधिक खपत या अतिरिक्त स्टॉक दिखाया गया, जिससे दूध पाउडर को कथित रूप से बाहर निकालने का रास्ता बनाया जा सके।

योजना के तहत, आरसीडीएफ दूध पाउडर उपलब्ध कराता है। आरसीडीएफ दूध की खरीद करता है और अतिरिक्त दूध को पाउडर में गुनगुने पानी में मिलाकर दूध तैयार किया जाता है। लेकिन आपूर्ति संकट ने अब खाद्य सुरक्षा से जुड़ी गंभीर समस्या भी पैदा कर दी है।

जब्त किए गए स्टॉक में एक्सपायर हो चुका दूध पाउडर भी शामिल था। नई खरीद में देरी के कारण स्कूलों में पिछले समय का बचा हुआ स्टॉक पड़ा हुआ है। शिक्षा विभाग ने स्कूलों को चेतावनी जारी करते हुए निर्देश दिया है कि दूध पाउडर का इस्तेमाल करने से पहले उसकी निर्माण तिथि और समाप्ति तिथि की अनिवार्य रूप से जांच की जाए।

मुफ्त ऑन ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

तैयारी के लिए समान अवसर मिल सके।

प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस पर लालकिले की प्राचीर से अपने संबोधन में मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग सुविधा उपलब्ध कराने की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री ने कहा था, कोचिंग कक्षाएं गरीब एवं मध्यम वर्ग के परिवारों पर बोझ हैं। हम विभिन्न परीक्षाओं के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग उपलब्ध कराएंगे।"

बैठक का उद्देश्य देशभर के छात्रों तक गुणवत्तापूर्ण शैक्षिणक सामग्री, विशेषज्ञ मार्गदर्शन और व्यवस्थित परीक्षा तैयारी की सुविधा पहुंचाने के लिए एक मजबूत राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म तैयार करना है।

28 में से ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

अन्य चार मुख्यमंत्रियों, सिक्किम के पी. एस. तमांग, पंजाब के भगवंत मान, ओडिशा के मोहन चरण माझी और राजस्थान के भजनलाल शर्मा के खिलाफ एक-एक मामला बताया गया है। हंसारिया द्वारा दाखिल 96 पृष्ठों की रिपोर्ट के मुताबिक, गंभीर आपराधिक मामलों का सामना कर रहे विधायकों का प्रतिशत सबसे अधिक पश्चिम बंगाल में 58 प्रतिशत है। राज्य के 292 विधायकों में से 170 के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले लंबित हैं। इसके बाद केरल में 57 प्रतिशत, आंध्र प्रदेश में 56 प्रतिशत, तेलंगाना में 49 प्रतिशत, झारखंड और ओडिशा में 45-45 प्रतिशत, बिहार में 42 प्रतिशत और महाराष्ट्र में 40 प्रतिशत विधायकों के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले लंबित हैं। रिपोर्ट के अनुसार, लोकसभा के 170 सांसदों, यानी 543 सदस्यों वाले सदन की कुल संख्या के करीब 31 प्रतिशत सांसदों के खिलाफ भी गंभीर आपराधिक मामले लंबित हैं।

कांग्रेस ने तय ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

इससे एक गंभीर सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या कांग्रेस कमजोर, अधूरे और कटे-छंटे संगठन के साथ भाजपा का मुकाबला करते हुए चुनाव जीत सकती है?

होर्मुज़ स्ट्रेट पर ईरान का ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

एंडी लिपो के अनुसार, कुवैत, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ने होर्मुज़ जलडमरूमध्य से तेल ले जाने और अपने तेल को गल्फ ऑफ ओमान में खतरे वाले इलाके के बाहर ग्राहकों के टैंकरों में ट्रांसफर करने के लिए कच्चे तेल के बहुत बड़े जहाज (वैरी लार्ज क्रूड कैरियर) किराए पर लिए हैं।

कुछ तेल टैंकरों ने ईरानी हमलों से बचने के लिए कई हफ्तों से अपने ट्रांसपॉण्डर बंद कर रखे हैं। केप्लर जैसे पारंपरिक व सामान्य ट्रैकिंग सिस्टम के लिए इस "डार्क ट्रैफिक" का पता लगाना मुश्किल हो सकता है, हालांकि सैटलाइट कभी-कभी इन जहाजों का पता लगा लेते हैं।

तथापि, अमेरिका की इस जलमार्ग पर व्यापक सैन्य निगरानी है और उसका दावा है कि उसके पास जहाजों की आवाजाही की कहीं अधिक विस्तृत जानकारी है। ऊर्जा मंत्री क्रिस राइट ने पिछले सप्ताह कहा था कि एक सप्ताह के दौरान जलडमरूमध्य से होकर गुजरने वाले तेल और इसके आसपास से दूसरे रास्ते से भेजे गए तेल को मिलाकर लगभग 1.5 करोड़ बैरल प्रतिदिन की आवाजाही हुई। यह युद्ध से पहले के करीब 2 करोड़ बैरल प्रतिदिन के औसत के काफी करीब है।

होर्मुज़ किसी भी पक्ष का पूरा नियंत्रण नहीं है। इस स्थिति ने राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप को यह दावा करने के लिए प्रेरित किया है कि अमेरिका का जलडमरूमध्य पर "पूरा नियंत्रण" है। लेकिन वास्तविकता इससे अधिक जटिल है।

ईरान अब भी लगातार जहाजों पर हमले कर रहा है और तेल की आवाजाही युद्ध से पहले के स्तर से काफी कम है। इससे अमेरिका के पूर्व नियंत्रण का दावा करना मुश्किल है।

साथ ही, ईरान भी अब यह विश्वसनीय रूप से दावा नहीं कर सकता कि जलडमरूमध्य पर उसका बिना किसी चुनौती के पूरा नियंत्रण है। पिकरिंग ने कहा, अगर उनका लक्ष्य 'प्रभारी' बनना है, तो मैं कहूंगा कि शुरुआत से ही उनका इस पर पूरी तरह नियंत्रण कभी नहीं था। उनके अनुसार, ईरान का उद्देश्य शायद पूरी तरह नियंत्रण रखने के बजाय डर बनाए रखना हो सकता है, जिससे यह दिखाया जा सके कि वह जहाजों की आवाजाही पर आर्थिक नुकसान पहुँचाने की क्षमता रखता है।

हालांकि, यह डर पैदा करने की उसकी क्षमता एक या दो महीने पहले की तुलना में कमजोर दिखाई दे रही है। अगर तेल की आवाजाही के बारे में अमेरिका के अनुमान मोटे तौर पर सही हैं, तो अब अधिक संख्या में टैंकर ईरान के प्रतिबंधों को चुनौती देने और अमेरिकी सुरक्षा में जलडमरूमध्य से गुजरने को तैयार हैं।

अब सबसे बड़ी अनिश्चितता ओमान से आ सकती है। मस्कट और तेहरान के बीच बातचीत चल रही है, जिसका उद्देश्य अमेरिका की सीधी भागीदारी के बिना जलडमरूमध्य से जहाजों की स्वतंत्र आवाजाही बहाल करना है। इस पहल से ट्रंप स्पष्ट रूप से नाराज हैं।

यह बातचीत एक बार फिर संतुलन बदल सकती है। बातचीत के जरिए स्ट्रेट को फिर से खोलने से अमेरिकी नौसेना की सुरक्षा की जरूरत कम हो सकती है और साथ ही समुद्री आवाजाही की सुरक्षा सुनिश्चित करने में ओमान की भूमिका बढ़ सकती है।

फिलहाल, हालांकि उपलब्ध सबूत एक संतुलित निष्कर्ष की ओर इशारा करते हैं: अमेरिका होर्मुज़ जलडमरूमध्य पर व्यावहारिक नियंत्रण की लड़ाई जीत रहा है, लेकिन उसे पूरा नियंत्रण नहीं मिला है। वहीं, ईरान के पास अब भी इतनी सैन्य क्षमता है कि वह जहाजों की आवाजाही को बाधित कर सकता है और कुछ हद तक अपना डर बनाए रख सकता है।

जैसा कि लिपो कहते हैं, इन खबरों को सावधानी से देखना चाहिए। लेकिन मुख्य सवाल पर, इस ट्रैंड को नजरअंदाज करना मुश्किल होता जा रहा है: ईरान ने जलडमरूमध्य पर कुछ हद तक नियंत्रण खो दिया है।

राष्ट्रदूत (एच.यू.एफ.) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, सुधर्मा, एम.आई.रोड़, जयपुर एवं सुधर्मा-II, लालकोठी शॉपिंग सेंटर, टोंक रोड़, जयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक:- राजेश शर्मा । आर.एन.आई. नं. 3641/57, ई-मेल-rastrdut@gmail.com कोटा कार्यालय:-पलायथा हाउस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन:2386031, 2386032, फैक्स:0744-2386033 बीकानेर कार्यालय:-कुंम्भाना हाउस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन:2200660, फैक्स: 0151-2527371 उदयपुर कार्यालय:-आयड, मेन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, 2418945, फैक्स: 0294-2410146 अजमेर कार्यालय:-घूघरा घाटी, जयपुर रोड,अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422, 226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय: एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन: 256906, 256907, फैक्स:01562-256908